गुटों को लेकर वार्ता होती रही है और मैं समझता हूं कि ये संगठन हिंसात्मक आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है । महोदय, यह सवाल इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, चूंकि माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं और... (व्यवधान)...

SHRI G. G. SWELL: Sir,...

श्री सुबोध कांत सहाय : महोदय, यह उम्मीद की जाती है कि असम-सरकार इन सारे संगठनों के साथ शांतिमय तरीके से वार्ता करके इनके सवालों को खतम करेगी, जिससे कोई हिंसात्मक आंदोलन भविष्य में न हो ।

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Chairman, Sir, in this very House there was a Private Member's Resolution on ULFA and Assam which I had the privilege to lead and for two successive days we had discussions. The only thing I wanted to draw your attention is that in February this year the hon. Minister has given the same reply. In March, he has given the same reply. In May, the same reply and this morning also he gave the same reply.

MR. CHAIRMAN: We have a consistent Minister.

SHRI VIREN J. SHAH: Permit me, Sir, it is a very serious question. At that time also he...

आप कहते हैं—उम्मीद की जाती है । that they were hoping.

श्री सभापति : भाई मेरे, आप जानते हैं, उम्मीद पर दुनियां कायम है ।

SHRI VIREN J. SHAH: Since then the situation is so deteriorating that lives are being lost and still the Government of India is not in a position to say anything concrete. They are hoping that the Government of Assam will do something. At that time also we have mentioned this thing and every week we talked to the Home Secretary. Is this leading to any result? Will the hon. Minister kindly say whether the situation has improved in Assam and in ULFA activities since May, 1990 when he gave the reply in this House till September, 1990? Is there any improvement? If so, what is the improvement? If there is no improvement, what is degeneration? What are they doing about it?

MR. CHAIRMAN: He wants to know whether there is any improvement in the last nine months.

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, इम्प्रूवमेंट तो रही है । मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उल्फा की गतिविधियां और भी जोर पर बढ़ी है और इसका कारण है कि वे इस वक्त यह चाहते हैं कि पोलिटिकल पावर असर्ट करें और हिंसा के द्वारा करें । इसमें कहीं मैं कोई छिपाने की बात नहीं करता हूं ।

SHRI VIREN J. SHAH: If you don't mind, the sovereignty of the country is under threat. That is why I am so serious about it.

श्री सुबोध कांत सहाय : नहीं मैं नहीं समझता, सर, कि इस तरह से कोई सावरेण्टि आफ दी कण्ट्री उल्फा से थेट होगा । उल्फा से असम की सरकार मुस्तैदी से निपटेगी और उसका मुकाबला करके उसका खातमा करेगी । ऐसी उम्मीद की जाती है और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यह कह रहा हूं ।

MR. CHAIRMAN: Q: No. 383.

राजस्थान में एक इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली परियोजना का स्थापित किया जाना

*383. **श्री राम दास अग्रवाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान में एक इलैक्ट्रानिक स्विचिग प्रणाली (ई.एस.एम.) परियोजना स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है, जिससे देश में ऐसे उद्योगों का संतुलित वितरण हो सके;

(ख) क्या सरकार ने ई.एस.एस. के लिये या तो सी-डॉट प्रौद्योगिकी या आयातित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के संबंध में भी कोई निर्णय लिया है;

(ग) भारत में पहले से ही ऐसी कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और वे किस क्षेत्र में है, कब स्थापित की गई हैं प्रत्येक परियोजना की लागत तथा प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(घ) क्या राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम ने ऐसी किसी परियोजना के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पहले ही आवेदन दिया था, यदि हां, तो कब और उसे अपेक्षित लाइसेंस प्रदान न किये जाने के क्या कारण थे; और

(ङ) राजस्थान में विद्यमान इलैक्ट्रो-मेकैनिकल टेलीफोन केन्द्रों का इलैक्ट्रानिक केन्द्रों के रूप में आधुनिकीकरण किये जाने तथा टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करने संबंधी वर्तमान प्रस्ताव क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार ने राजस्थान में सी. डॉट–512 पोर्ट किस्म की इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली के विनिर्माण के लिए एक यूनिट की स्थापना करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है । इस प्रणाली का उत्पादन केन्द्र सरकार के एक उपक्रम मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा द्वारा किया जाना है ।

(ख) सरकार ने ई.एस.एस. के लिए सी-डॉट की स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग का निर्णय लिया है ।

(ग) भारत में कुल 27 परियोजनाएं पहले से ही काम कर रही हैं । इसमें 4 इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. की यूनिटें, 3 अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 9 राज्य क्षेत्र में, 3 संयुक्त क्षेत्र में और 8 निजी क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं । इन परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है । (नीचे देखिए)

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

(ङ) योजना लक्ष्यों के मसौदे में, मियाद समाप्त और बेकार हुए इलेक्ट्रो-मकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य शामिल है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार और 180 स्थानीय इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज चालू करके 28129/32500 स्विचन क्षमता / सीधी एक्सचेंज लाइनें चालू करने की योजना है । इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में 83 सार्वजनिक टेलीफोन और शहरी क्षेत्र में 200 सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

3–9–90 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों का उत्पादन करने वाले विनिर्माताओं की सूची ।

1. आई. टी. आई. (केन्द्र सरकार का उपक्रम)

	परियोजना	निवेश	स्थापना का वर्ष
		(करोड़ रु.)	
1	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. मनकापुर मद : सभी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियां उत्पादन क्षमता: 500000 लाइनें प्रति वर्ष	219	1985
2.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. (बंगलौर) मद : सभी की स्विचिंग प्रणालियां उत्पादन क्षमता : 200000 लाइनें प्रति वर्ष लाइसेंस्ड क्षमता : 500000 लाइनें प्रति वर्ष	9.07	1988

परियोजना	निवेश	स्थापना का वर्ष
	(करोड़ रु०)	
3. इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज लि० (माडल संयंत्र बंगलौर) मद : सभी प्रकार की स्विचिंग प्रणालियां उत्पादन क्षमता : 100000 लाइनें प्रति वर्ष	16.82	1988
4. इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज लि० (पालघाट) मद : डीडीएएक्स (60के)/रैक्स (50के) इपीएबीएक्स/ईपीए एक्स (40 के) उत्पादन क्षमता : 150000 लाइनें प्रति वर्ष लाइसेंस्ड क्षमता : 260000 लाइनें प्रति वर्ष	6.67.5	1985

ईएसएम (128 पोर्ट रैक्स) बनाने वाली अन्य यूनिटें
निवेश : प्रत्येक में 2.5 करोड़ रुपए
संस्थापित क्षमता : प्रत्येक विनिर्माता की 20000 प्रति वर्ष
विनिर्माता–89–90 में स्थापित

	क्षेत्र
1. गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी लि०	राज्य सरकार का उपक्रम
2. राजस्थान कम्यूनिकेशन लि०	राज्य सरकार का उपक्रम
3 भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	केन्द्रसरकार का उपक्रम
4 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	केन्द्र सरकार का उपक्रम
5. कोन्टीनेंटल डिवाइस इंडिया लि०	निजी कम्पनी
6. इंडकेम इलेक्ट्रानिक्स लि०	निजी कम्पनी
7. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	निजी कम्पनी
8. जे एंड के टेलीकाम	राज्य सरकार का उपक्रम
9. कर्नाटक टेलीफ़ोन लि०	राज्य सरकार का उपक्रम
10. केरल राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (केटटार)	राज्य सरकार का उपक्रम
11. लार्सन एंड टूबरो लि०	निजी कम्पनी
12. महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रानिक्स निगम लि०	राज्य सरकार का उपक्रम
13. नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी लि०	निजी कम्पनी
14. रेडियो इलेक्ट्रानिक्स	राज्य सरकार का उपक्रम
15. राजस्थान टेलीमेटिक्स (पी) लि०	निजी कम्पनी
16. यूनाइटेड टेलीकाम लि०	निजी कम्पनी
17. मोदी टेलीमेटिक्स लि०	निजी (संयुक्त उपक्रम)
18. इन्यू एम इंडस्ट्रीज	निजी कम्पनी
19. क्राम्पटन ग्रिवीज लि०	निजी कम्पनी
20. गुजरात कम्यूनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक्स लि०	राज्य सरकार का उपक्रम
21. पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि०	राज्य सरकार का उपक्रम
22. टेलीमेटिक्स सिस्टम्स लि०	संयुक्त उपक्रम
23. हार्डन नेटवर्क्स लि०	संयुक्त उपक्रम

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा राजस्थान में सी-डोट-512 टाइप का यूनिट राजस्थान में लगाएगी, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए उन्होंने स्थान का चयन कर लिया है और उसमें कितना इंवेस्टमेंट लगाने की योजना बनाई है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राजस्थान में जगह तय हो गई है और जहां तक पूजी-निवेश का है, चूंकि यह राजस्थान सरकार का अंडरटेकिंग है, तो जब वह देगी, उस पर कार्यवाही होगी ।

SHRI T. A. MOHAMMAD SAQHY: Regarding C-DOT technology I had asked a Starred Question some three days ago. I would like to know what happened to the probe. The CBI has been asked to probe into the Rs. 200 crore deal. How far they have progressed in the matter of probe?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, हालांकि इस सवाल से यह संबंधित नहीं है, लेकिन सी बी आई० से इन्क्वायरी हो रही है, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री सभापति : क्वैश्चन 384

Representations from the PTI and the UNI agencies for the revision of subscriptions by the AIR and DD

*384. SHR G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are considering the representations from the PTI and the UNI news agencies for the revision of subscriptions by the AIR and Doordarshan to meet the rising cost of operations of the news agencies including implementation of the Bachawat Wage AWARD; and

(b) if so, by when a decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): (a) Yes, Sir.

(b) An Inter-Departmental Committee set up for this purpose has since submitted its report. Action has been initiated on receipt of the report. Since consultation with another Ministry is involved, no specific date can be indicated.

SHRI G. Y. KRISHNAN: Sir, the Minister has replied that the Committee has since submitted its report. Sir, the Government is paying higher subscriptions through AIR and Doordarshan to the news agencies for meeting the cost of operations and for the implementation of the Bachawat award. The UNI management was paid Rs. 35 lakhs earlier and recently Rs. 60 lakhs as advance. Despite all this, the UNI management has denied the statutorily prescribed Grade I pay scales to the editors of the UNI. As the UNI management is getting substantial grants and loans from the Government, will the Minister assure this House about the implementation of the Bachawat award by way of giving the Grade I pay scales to the editors of the UNI with effect from 1-1-88? The Government should direct the UNI management to comply with the Government's order in this respect. Will the honourable Minister assure ths House in this regard?

SHRI P. UPENDRA: Sir, the news agencies have requested for an increase in the subscription rates to meet their increased expenditure including the cost of implementation of the Bachawat award. That is why the Government has sympathetically considered this aspect. We have made up our mind and some recommendation has already been made in this regard to the Finance Ministry and in the next few days we will issue the orders.

As far as the implementation of the Bachawat award is concerned, we have been impressing on the newspapers as well as the news agencies that the recommendations must be implemented. But these are all independent organisations and autonomous bodies and, therefore, the Government cannot impose its view on them. But we are trying our best to impress upon